भारत के आर्थिक अस्वस्थता का केंद्र बिंदु

लेखक - मनमोहन सिंह (भारत के पूर्व प्रधानमंत्री)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-III (भारतीय अर्थव्यवस्था) से संबंधित है।

द हिन्दू

18 नवंबर, 2019

"संस्थानों में नागरिकों का अविश्वास और सरकार में विश्वास की कमी लंबे समय तक मंदी का कारण बनी हुई है।"

भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति गहरी चिंताजनक है। मैं यह बात विपक्षी राजनीतिक दल के सदस्य होने के नाते नहीं कह रहा हूँ, बल्कि मैं इस देश के एक नागरिक और अर्थशास्त्र का छात्र रहने के नाते कह रहा हूँ। अब तक इतने सारे तथ्य हमारे पास उपलब्ध हो गये हैं जिससे हम समझ सकेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था मंदी के दौर से गुज़र रही है। उदाहरण के लिए, नॉमिनल जीडीपी विकास 15 साल के निम्न स्तर पर है, बेरोजगारी 45 साल की ऊँचाई पर है; घरेलू खपत चार-दशक के निम्न स्तर पर है, बैंकों में बैड लोन एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर हैं; बिजली उत्पादन में वृद्धि 15 साल के निचले स्तर पर है। देखा जाए तो इस तरह की उतार-चढ़ाव की सूची काफी लंबी और परेशान करने वाली है। लेकिन अर्थव्यवस्था की चिंताजनक स्थिति इन आँकड़ों के कारण नहीं है, बल्कि ये सरकार में विश्वास की कमी के कारण है जो देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचा रहा है।

देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी कार्य और अपने समाज की स्थिति का प्रतिबिंब है। किसी भी अर्थव्यवस्था का कामकाज़ अपने लोगों और संस्थानों के बीच आदान-प्रदान और सामाजिक संबंधों के संयुक्त सेट का परिणाम है। आपसी विश्वास और आत्मविश्वास लोगों के बीच ऐसे सामाजिक लेनदेन का आधार हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। हमारे भरोसे का सामाजिक ताना-बाना अब कमज़ोर पड़ गया है।

उद्योगपति भय में जीते हैं

हमारे समाज में आज डर का माहौल है। कई उद्योगपति मुझे बताते हैं कि वे सरकारी अधिकारियों द्वारा उत्पीड़न के डर में रहते हैं। प्रतिदंड के डर से बैंकर नए ऋण प्रदान करने में रुचि नहीं दिखा रहे हैं। अप्रत्यक्ष उद्देश्यों की असफलता के डर से उद्यमी नए प्रोजेक्ट लगाने में हिचकिचाते हैं। प्रौद्योगिकी स्टार्ट-अप, आर्थिक विकास और नौकरियों का एक महत्त्वपूर्ण नया इंजन, निरंतर निगरानी और गहन संदेह की छाया में रहते हैं। सरकार और अन्य संस्थानों में नीति निर्धारक सत्य बोलने या बौद्धिक रूप से ईमानदार नीतिगत चर्चा में संलग्न होने से डरते हैं।

आर्थिक विकास के कारक के रूप में कार्य करने वाले लोगों में गहरा भय और अविश्वास बना हुआ है। जब ऐसा अविश्वास होता है तो यह समाज में आर्थिक लेनदेन पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। जब लोगों और संस्थानों के बीच लेन-देन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है तो आर्थिक गतिविधि मंदी की ओर जाता है और अंततः ठहराव आ जाता है। नागरिकों के बीच भय, अविश्वास और विश्वास की कमी की यह खतरनाक स्थिति हमारी तेज़ आर्थिक मंदी का एक मूल कारण है।

हमारे समक्ष लाचारी की भी स्थिति व्याप्त है। पीड़ित नागरिक अपनी शिकायतों को उचित स्थान तक नहीं ले जा पाते हैं। मीडिया, न्यायपालिका, नियामक अधिकारियों और जाँच एजेंसियों जैसे स्वतंत्र संस्थानों में जनता का भरोसा बुरी तरह से चरमरा गया है। विश्वास के क्षरण के साथ, लोगों को गैरकानूनी कर उत्पीड़न या अनुचित नियमों के खिलाफ शरण लेने के लिए एक समर्थन प्रणाली की कमी

है। इससे उद्यमी नई परियोजनाओं को शुरू करने और रोज़गार सृजन के लिए जोखिम नहीं उठाना चाहते हैं। गहरा अविश्वास, व्यापक भय और हमारे समाज में निराशा की भावना का विषाक्त संयोजन आर्थिक गतिविधि को बेहद नुकसान पहुँचा रहा है।

यह संदेह कि हर उद्योगपति, बैंकर, नीति निर्धारक, नियामक, उद्यमी और नागरिक सरकार को धोखा देंगे जिससे हमारे समाज में विश्वास का पूर्ण विघटन हुआ है। इसने आर्थिक विकास को रोक दिया है, बैंकर उधार देने में असमर्थ हो गए हैं, उद्योगपति निवेश करने में असमर्थ हैं और नीति निर्धारक कार्य करने में असमर्थ हैं।

मोदी सरकार ने हर किसी को संदेह और अविश्वास के दागी चश्मे के माध्यम से सब कुछ देखा है जिसके कारण पिछली सरकारों की हर नीति को अब खराब इरादे के रूप में माना जाता है, प्रत्येक स्वीकृत ऋण को अवांछनीय माना जाता है और प्रत्येक नई औद्योगिक परियोजना को खराब माना जाता है। सरकार ने खुद को एक रक्षक के रूप में सब के सामने पेश किया है जो मूर्खतापूर्ण नीतियों का सहारा लेते हुए विमुद्रीकरण जैसी नीति को अंज़ाम दे रहा है, जो न सिर्फ वैचारिक रूप से गलत साबित हुआ बल्कि यह विनाशकारी भी साबित हुआ है। सरकार को यह समझना चाहिए कि हर किसी को गलत ठहराना और 'अच्छा-बनाम-बुराई शासन' सिद्धांत स्वस्थ आर्थिक विकास के लिए एक नुस्खा नहीं हो सकता है।

आर्थिक विकास में सामाजिक विश्वास की भूमिका को अच्छी तरह से प्रलेखित किया गया है, जो एडम स्मिथ के समय से लेकर व्यावहारिक अर्थशास्त्र के आधुनिक समय के अनुशासन तक है। विश्वास के हमारे सामाजिक ताने-बाने को तोड़ना हमारे मौजूदा आर्थिक संकट का केंद्र बिंदु है। आर्थिक विकास को पुनर्जीवित करने के लिए यह बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भय और अविश्वास के कारण अलग हो चुके सामाजिक ताने-बाने को फिर से सशक्त किया जाए। व्यापारियों, पूँजी प्रदाताओं और श्रमिकों को भयभीत कराने की बजाय आत्मविश्वास और अति उत्साह महसूस करना बहुत महत्त्वपूर्ण है।

वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था एक अनिश्चित स्थिति में है। बेहतर परिणाम नहीं मिल रहे हैं। घरेलू खपत धीमी हो रही है। खपत के एकसमान स्तर को बनाए रखने के लिए लोग अपनी बचत में कमी कर रहे हैं।

मुद्रास्फीतिजनित मंदी का खतरा

वास्तविक चिंता का विषय यह है कि सबसे हालिया खुदरा मुद्रास्फीति की संख्या में तेज़ वृद्धि हुई है, विशेषकर खाद्य मुद्रास्फीति के आँकड़ों में। आने वाले महीनों में खुदरा मुद्रास्फीति में और भी वृद्धि होने की उम्मीद है। स्थिर माँग और उच्च बेरोज़गारी के साथ संयुक्त मुद्रास्फीति में निरंतर वृद्धि से अर्थशास्त्री मुद्रास्फीतिजनित मंदी आने की संभावना प्रकट कर रहे है जो एक खतरनाक क्षेत्र है और जहाँ से बड़ी अर्थव्यवस्थाओं को पुनर्प्राप्त करना बहुत कठिन हो जाता है। हालाँकि हम वर्तमान में अभी तक संघर्ष के क्षेत्र में नहीं आए हैं, लेकिन जैसा कि मौद्रिक नीति का प्रभाव मौन है, हमें राजकोषीय नीति के उपायों के माध्यम से खपत की माँग को बहाल करने के लिए जल्दी से बेहतर पहल करना होगा।

मेरी धारणा भारत की नाजुक आर्थिक स्थिति राजकोषीय नीति के माध्यम से माँग को बढ़ाने और हमारे समाज में आर्थिक प्रतिभागियों में विश्वास और आत्मविश्वास को प्रेरित करके 'सामाजिक नीति' के माध्यम से निजी निवेश को पुनर्जीवित करने की जुड़वाँ नीति से जुड़ी है।

भारत अब एक 3 ट्रिलियन डॉलर का वैश्विक आर्थिक महाशक्ति है जो काफी हद तक निजी उद्यम द्वारा संचालित है। यह इतनी भी छोटी अर्थव्यवस्था नहीं है जिसे केवल इच्छा मात्र से या रंगीन सुर्खियों और शोर करने वाली मीडिया टिप्पणी के माध्यम से प्रबंधित किया जा सके। किसी भी प्रकार का छल 1.2 बिलियन लोगों की + 3-ट्रिलियन बाज़ार अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन और विश्लेषण को छिपा नहीं सकती है।

अफसोस की बात है कि यह आत्म-संकटग्रस्त आर्थिक चोट ऐसे समय में आई है जब भारत के लिए पूँजीकरण के लिए वैश्विक अर्थव्यवस्था में एक अनूठा और उपयुक्त क्षण मौजूद है। चीन की अर्थव्यवस्था और निर्यात के धीमे होने से भारत के लिए एक बड़ा निर्यात अवसर खुल गया है। भारत को भय, अविश्वास और निराशावाद के मौजूदा माहौल से दूर हटकर विश्वास और आर्थिक गतिशीलता के माहौल को बढ़ावा देते हुए निर्यात को बढ़ावा देने के विषय में विचार करना चाहिए।

सरकार के पास लोकसभा में पूर्ण बहुमत है और वैश्विक तेल की कीमतें कम होने के कारण यह समय भारत को आर्थिक विकास के अगले चरण में ले जाने और सैकड़ों लाखों युवाओं के लिए नए रोज़गार सृजित करने का एक अवसर प्रदान करता है। मैं प्रधान मंत्री से उद्योगपतियों और उद्यमियों के अपने गहरे निहित संदेह को अलग करने और हमें एक आश्वस्त और पारस्परिक रूप से भरोसेमंद समाज में वापस लाने का आग्रह करता हूँ जो हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में मदद कर सकता है।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-

1. वर्तमान भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति की संख्या में वृद्धि हुई है।
2. भारतीय अर्थव्यवस्था की नॉमिनल जी.डी.पी. विकास दर 15 साल के निम्न स्तर पर है।
3. विमुद्रीकरण और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की शुरूआत ने अर्थव्यवस्था के विकास को मंद किया है।

उपर्युक्त में से कौन-से कथन सत्य हैं?

(a) 1 और 2

(b) 2 और 3

(c) 1 और 3

(d) 1, 2 और 3

Expected Questions (Prelims Exams)

1. Consider the following statements in the context of the recent Indian economy.

1. In the current Indian economy, the number of inflation has increased
2. The nominal GDP growth rate of the Indian economy is at a 15-year low.
3. Demonetisation and introduction of Goods and Services Tax have slowed the growth of the economy.

Which of the above statements are correct?

(a) 1 and 2

(b) 2 and 3

(c) 1 and 3

(d) 1, 2 and 3

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्न: "किसी भी अर्थव्यवस्था का कामकाज़ अपने लोगों और संस्थानों के बीच आदान-प्रदान और सामाजिक संबंधों के संयुक्त सेट का परिणाम है। आपसी विश्वास और आत्मविश्वास लोगों के बीच ऐसे सामाजिक लेनदेन का आधार हैं जो आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हैं। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं? उपयुक्त तर्कों के माध्यम से अपने मत की पुष्टि कीजिए:- (250 शब्द)

The functioning of any economy is the result of a joint set of exchanges and social relations between its people and institutions. Mutual trust and confidence are the basis of social transactions between people that promote economic development. To what extent you agree with this statement? Verify your opinion through the appropriate arguments: - (250 words)

नोट : 16 नवम्बर को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1 (c) होगा।